

“भारत में सूची या व्यापार का उपयोग रणनीतिक नीति उपकरण के रूप में किया जाना चाहिए ताकि भारतीयों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों में शेयरधारक बनाया जा सके।”

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई 2.0) का भारत में स्वागत किया गया है, भले ही इसके इक्विटी ढांचे में भारतीय सार्वजनिक हिस्सेदारी शामिल हो या न हो। हालाँकि, दुनिया में Microsoft, Google, Facebook और Twitter जैसी इंटरनेट मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs) के उद्भव के साथ एक संरचनात्मक परिवर्तन आया है जो विनर-टेकस-आल (Winner-takes-all) प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल पर आधारित हैं। इन फर्मों को अनिवार्य रूप से असमान गतिशीलता द्वारा चित्रित किया जाता है, क्योंकि ये अपने मेजबान देशों के साथ-साथ खुद को भी सबसे अधिक लाभ प्रदान करते हैं। यह स्थिति नीतिगत प्रतिक्रिया की मांग करती है।

शायद यही एक कारण है कि जिसके कारण चीन ने इंटरनेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रतिबंधित कर दिया। इसके चलते चीन ने 20 वैश्विक इंटरनेट नेताओं में से नौ का निर्माण किया। चीन रणनीतिक रूप से क्विड प्रो क्वो नीति (quid pro quo policy) यानी वस्तुओं या सेवाओं का आदान-प्रदान, जिसमें एक हस्तांतरण दूसरे पर प्रासंगिक है; 'एक एहसान के बदले एहसान' को लागू करता है। एमएनसी फर्मों को बाजार पहुंच के बदले में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, पेटेंट साझा करने और चीनी साझेदारों के साथ 50:50 संयुक्त उद्यमों की शर्त माननी पड़ती है। हमारी राजनीतिक प्रणाली को देखते हुए, भारत को स्पष्ट रूप से अधिक वांछनीय परिणाम प्राप्त करने के लिए एक नई एफडीआई 2.0 नीति का पालन करने की आवश्यकता होगी।

एफडीआई 2.0 को भारतीय उपभोक्ताओं, सरकार और निवेशकों सहित सभी हितधारकों के हितों का सामंजस्य बनाना चाहिए। एफडीआई 2.0 भारत में सूची या व्यापार को एक रणनीतिक नीति उपकरण के रूप में तैनात कर सकता है ताकि भारतीय नागरिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों जैसे कि Google, Facebook, Samsung, Huawei और अन्य में शेयरधारक बन सकें, इस प्रकार वे सबसे ऊपर रह कर अपने लिए प्लेटफार्मों और कंपनियों का निर्माण कर सकते हैं। यह सभी के लिए समान है, क्योंकि भारतीय उपभोक्ता बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार मूल्य में योगदान देते हैं।

1978 में, भारत सरकार ने एक नीति अपनाई जिसमें 100% विदेशी स्वामित्व वाली कंपनियों द्वारा इक्विटी डाइल्यूशन (equity dilution; कंपनी के मौजूदा शेयरधारकों के स्वामित्व में कमी, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी नई इक्विटी जारी करती है) की आवश्यकता थी। इसके कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची और इसके बाद कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों और भारतीय शेयरधारकों दोनों को शानदार रिटर्न मिला। अब अनुमान लगाया गया है कि अकेले बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भारतीय सहायक कंपनियों को सूचीबद्ध करने से इक्विटी बाजार पूंजीकरण में 50 लाख करोड़ रूपए का इजाफा हो सकता है।

इससे पूंजी बाजार और गहरा हो सकता है और मूल्यांकन अधिक उचित होगा। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सूची या व्यापार बहुतायत मेक इन इंडिया में समृद्धि का प्रसार करने के लिए एक शक्तिशाली विस्तार बन सकता है। 1978 के विपरीत, हम यहां जो प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, वे प्रोत्साहन, अधिक पूंजी बाजार के अनुकूल और मैक्सिको, चीन, बांग्लादेश और अन्य देशों द्वारा अपनाये गये प्रथाओं के अनुरूप हैं।

भारत के लिए एक रोड मैप

भारत प्रस्तावों के निम्नलिखित सेट को लागू कर सकता है: प्रस्ताव 1 (भारत में सूची): अधिकांश (51% से अधिक) विदेशी स्वामित्व वाली भारतीय-सूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियां घरेलू कंपनी कर दर के योग्य हो सकती हैं, जबकि असूचीबद्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों

को उच्च कर के अधीन किया जा सकता है। बांग्लादेश, वियतनाम और थाईलैंड जैसे कई देशों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा लिस्टिंग या सूचीकरण को आकर्षित करने के लिए कर प्रोत्साहन का उपयोग किया है।

मैक्सिको क्रॉस लिस्टिंग को आकर्षित करने में सबसे सफल रहा है। उदाहरण के लिए, एबी इनबेव, कोका-कोला, वॉलमार्ट और सिटीग्रुप मैक्सिको में सूचीबद्ध हैं। इस प्रस्ताव की सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, सरकार को अपने सूचीबद्ध भारतीय समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 100% बहुराष्ट्रीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अनुमति देने की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी जो भारतीय शेयरधारकों के लिए अर्जित मूल्य को खत्म कर देगी।

प्रस्ताव 1, अपने आप, इंटरनेट बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उचित मूल्य में भारतीय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त नहीं करेगा। ऐसा राजस्व बुकिंग में जटिल मुद्दों के कारण होगा जिससे भारतीय सहायक कंपनियों को कम लाभ मिलेगा। इसलिए, मूल MNC के शेयरों के स्वामित्व में भारतीय निवेशक की भागीदारी को सक्षम करने के लिए प्रस्ताव 2 के माध्यम से अतिरिक्त पहल की आवश्यकता है।

प्रस्ताव 2 (भारत में व्यापार यानी अमेरिकी डॉलर के मूल्य वाले मूल MNC शेयरों को भारतीय बाजारों पर व्यापार के लिए प्रस्तुत किया जाना):- इस प्रस्ताव में, भारतीय निवेशक मूल MNC (जहां वैश्विक लाभ और मूल्य समेकित होते हैं) के शेयर खरीद सकते हैं। इसे + 250,000 लिबरलाइज्ड रैमिटेस स्कीम (LRS) की सीमा के भीतर अनुमति दी जा सकती है। भारतीय बॉरोअर्स केवल S - P 500 स्टॉक स्वीकार कर सकते हैं। मैक्सिकन स्टॉक एक्सचेंज अन्य स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध अंतरराष्ट्रीय शेयरों के व्यापार की अनुमति देता है। भारत ऐसे मॉडलों की प्रतिकृति बना सकता है।

मैक्सिको से सीखना

प्रस्ताव 2 के सफल कार्यान्वयन के लिए, भारत सरकार को निम्नलिखित उपायों को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता हो सकती है:-

भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार को मैक्सिको की तर्ज पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली को लागू करने के लिए अनुमति देना। भारत में व्यावसायिक हितों के साथ S-P 500 में मूल MNCs को भारत में अपने शेयरों के व्यापार की सुविधा के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। डछे आसानी से सहमत होंगे क्योंकि यह भारत में लिस्टिंग की परिकल्पना नहीं करता है।

कराधान के प्रयोजनों के लिए, तुलनीय घरेलू और विदेशी प्रतिभूतियों में लेनदेन के बीच कोई अंतर नहीं किया जाना चाहिए। GIFT सिटी/NSE/BSE में विदेशी स्टॉक खरीदने के लिए LRS कार्यान्वयन को सरल बनाया जा सकता है और सिंगल क्लिक कार्यक्षमता के रूप में काम किया जा सकता है।

बेहतर जोखिम समायोजित रिटर्न प्राप्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय शेयरों में अपने पोर्टफोलियो के विविधीकरण के मूल्य के बारे में भारतीय निवेशकों को शिक्षित करना।

सरकार भारतीय ई-केवाईसी का उपयोग करके अल्ट्रा-लो कॉस्ट ($\leq 0.04\%$) S-P 500 इंडेक्स फंड जैसे एडमिरल शेयर (VFIAX) और ETF की सुविधा दे सकती है। भारतीय एमएफ 0.54% से 2% तक शुल्क लेते हैं। वे कम से कम 13 गुना अधिक महंगे हैं।

प्रस्ताव 2 के लिए, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे अमेरिकी एस्टेट करों से संबंधित होने की आवश्यकता है। भारतीय नागरिकों के लिए, अमेरिकी संपत्ति कर / 40% +60,000 के पोर्टफोलियो मूल्य से ऊपर लागू होते हैं।

इस बोझ को कम करने के लिए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) पेरेंट एनएनसी स्टॉक रखने के लिए एक सॉवरिन ट्रस्ट डिजाइन कर सकता है। एनएसडीएल तब भारतशारों को खुदरा निवेशकों को जारी कर सकता था। भारत सरकार के नुमाइंदों को मूल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मतदान का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, सरकार हमारे एनएसडीएल/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) सिस्टम के अनुरूप विदेशी स्टॉक रखने के लिए एक श्रुती तरह से डिस्कलोज्ड मॉडलश उपलब्ध करा सकती है। प्रचलित ओम्निबस मॉडल में यू.एस. ब्रोकर डिफॉल्ट का जोखिम होता है क्योंकि निवेशकों के शेयर यू.एस. ब्रोकर के नाम पर होते हैं। इस कारण से, यह भारत में उच्च कर देनदारियों को भी जन्म दे सकता है।

एनएनसी के भारतीय इक्विटी स्वामित्व में वृद्धि, विविधीकरण लाभ प्रदान करेगी और भारतीयों को अधिक समृद्ध बनाएगी। म्यूचुअल फंड के माध्यम से धन वितरण से भारतीय समाज के लाभ के लिए नवीन विचारों, उद्यमशीलता, रोजगार, उपभोग, उच्च करों, सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे का एक अच्छा चक्र तैयार होगा। MNC अपने निवेशक आधार का विस्तार करते हुए भारतीय उपभोक्ताओं की सद्भावना अर्जित करेंगे। दूसरे शब्दों में, यह सभी हितधारकों के लिए एक जीत है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment & FDI)

क्या है?

- यह एक समूह द्वारा किसी एक देश के व्यवसाय या निगम में स्थायी हितों को स्थापित करने के इरादे से किया गया निवेश होता है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आर्थिक विकास का एक प्रमुख वाहक और देश में आर्थिक विकास के लिये गैर-ऋण वित्त का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से घरेलू अर्थव्यवस्था में नई पूंजी, नई प्रौद्योगिकी आती है और रोजगार के मौके बढ़ते हैं।

लाभ

- अधिक विदेशी निवेश होने से बीमा कंपनियां अपना विस्तार करेंगी और नए दफ्तर भी खुलेंगे। इसकी वजह से अधिक नौकरियां पैदा होंगी, जो देश में रोजगार को बढ़ावा देंगी।
- इसकी वजह से नए ब्रोकर भी आएंगे, जो बाजार को इश्योरेंस के बारे में और बेहतर तरीके से बता पाएंगे।
- अधिक कंपनियां होने के कारण उनमें प्रतिस्पर्धा का दौर भी चल सकता है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे।
- हर कंपनी अधिक से अधिक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहेगी, जिसके चलेगी प्रोडक्ट न सिर्फ सस्ते होंगे, बल्कि उनकी क्वालिटी भी सुधरेगी।

नुकसान

- आम जनता को नुकसान- अनस्किलड (अकुशल) लोगों की जीविका पर खतरा एफडीआई से अकुशल श्रमिकों को सबसे अधिक नुकसान होता है। जितनी अधिक एफडीआई की सीमा होगी, उतना ही अधिक अकुशल श्रमिकों को नुकसान होगा।
- बड़ी कंपनियां स्किलड लोगों को तो नौकरी मुहैया कराएंगी, लेकिन अनस्किलड लोगों को नौकरी देने में मुकरेंगी।
- छोटी कंपनियों का भी अधिग्रहण होने लगेगा, जिससे अनस्किलड लोगों के लिए नौकरी पाना काफी मुश्किल हो जाएगा।

- कंपनियां सस्ता सामान बेचकर ग्राहकों को लुभाएंगी, जिसका मुकाबला छोटी कंपनियां नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से उनके अस्तित्व पर खतरा भी मंडरा सकता है।
- बड़ी विदेशी कंपनियां मौजूदा कंपनियों का अधिग्रहण कर बाजार पर अपना कब्जा कर सकती हैं।

अप्रैल जून तिमाही में एफडीआई

- चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 28 प्रतिशत बढ़कर 16.33 अरब डॉलर पर पहुंच गया। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है।
- वित्त वर्ष 2018-19 की इसी तिमाही में देश में 12.75 अरब डॉलर का एफडीआई आया था।
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में 2.80 अरब डॉलर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में 2.24 अरब डॉलर, दूरसंचार में 4.22 अरब डॉलर और कारोबार में 1.13 अरब डॉलर का एफडीआई आया।
- इस दौरान सिंगापुर से सबसे ज्यादा 5.33 अरब डॉलर एफडीआई आया। इसके बाद 4.67 अरब डॉलर के साथ मॉरीशस, 1.45 अरब डॉलर के साथ नीदरलैंड और 47.20 करोड़ डॉलर के साथ जापान का स्थान रहा। सरकार ने हाल ही में कुछ क्षेत्रों में एफडीआई नियमों में ढील दी है।
- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिंगल ब्रैंड रिटेल सहित कई सेक्टरों में FDI के नियमों में ढील को मंजूरी दी।
- केंद्र सरकार ने कोयला खनन गतिविधियों तथा कॉन्ट्रैक्ट मैनुफैक्चरिंग (किसी कंपनी द्वारा किसी अन्य कंपनी के लिए उसके ब्रैंड या लेवल के तहत माल का उत्पादन करना) में 100% एफडीआई को भी मंजूरी प्रदान की।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कैम्पेन को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत कैबिनेट ने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में 26% एफडीआई को मंजूरी दी। यह देश में पहले केवल प्रिंट मीडिया के लिए था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. भारत सरकार एफ.डी.आई. 2.0 तैयार करने पर विचार कर रही है। एफ.डी.आई. 2.0 के लिए रोड मैप तैयार करने वाले कथनों पर विचार कीजिए:-

1. सरकार को अपने सूचीबद्ध भारतीय समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए 100% बहुराष्ट्रीय स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अनुमति देने की आवश्यकता है।
2. ब्रिटेन, क्रॉस लिस्टिंग को आकर्षित करने में सबसे सफल रहा है, जिससे सीख कर भारत एक अच्छा रोडमैप बना सकता है।
3. विदेशी स्टॉक रखने के लिए एक पूरी तरह से डिस्क्लोज्ड मॉडल उपलब्ध कराया जा सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

- (a) 1 और 2 (b) केवल 2
(c) 1 और 3 (d) केवल 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Government of India is considering preparation of F.D.I. 2.0. Consider the statements that prepare the road map for FDI 2.0: -

1. The government needs to allow 100% multinational subsidiaries to compete with their listed (Indian counterparts).
2. Britain, has been the most successful in attracting Cross listings, learning from which India can make a good roadmap.
3. A fully disclosed model can be provided to hold foreign stock.

Which of the statements given above is / are correct?

- (a) 1 and 2 (b) 2 only
(c) 1 and 3 (d) 3 only

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: 'भारत में एफडीआई के नए स्वरूप को आकर्षित करने हेतु नीतिगत एवं ढांचागत परिवर्तन लाने होंगे तथा वैश्विक उदाहरणों को अपनाना होगा।' इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? चर्चा कीजिए।

'To attract a new form of FDI in India, policy and structural changes have to be brought and global examples will have to be adopted.' To what extent do you agree with this statement? Discuss (250 Words)

नोट : 3 अक्टूबर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।